ईएसआई अस्पताल: स्टाफ़ की आधी अधूरी भर्ती

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर मोर्चा के 16-30 नवम्बर अंक में प्रकाशित किया गया था कि स्थानीय एन एच-3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई इमारत करीब 900 करोड़ की लागत से साढे 6 वर्ष में बनकर खड़ी तो हो गयी, आंशिक रूप से चालू भी हो गयी, परन्तु इसमें 500 बेड के लिये स्टाफ़ केवल नाम मात्र को ही है। इसकी पूरी तालिका उस अंक में प्रकाशित की गयी थी।

दिनांक 7.12.15 को ईएसआई निगम ने नियमित स्टाफ़ भर्ती के लिये विज्ञापन निकाला। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2016 रखी गयी है। दो विज्ञापनों के द्वारा निगम ने 17 स्टेनो ग्राफ़र, 91 कलर्क, 48 बहु-उपयोगी, 66 स्टाफ़ नर्स, एक थेरापिस्ट, 4 फ़ार्मासिस्ट, 6 ओटी सहायक, 5 जूनियर रेडियोग्राफ़र, 30 नर्सिंग ऑर्डरली, 4 ड्रेसर,7 रसोइये इत्यादि, 4 प्लास्टर सहायक, 3 ईसीजी तकनीशियन, एक मेडिकल सोशल वर्कर, एक जूनियर एमआरटी तथा एक आयुर्वेदिक फ़ार्मासिस्ट।

फ़रीदाबाद वालों को इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उक्त सभी नियुक्तियां केवल गुड़गांव और मानेसर के अस्पतालों के लिये हैं। इनमें से एक भी नियुक्ति यहां के लिये नहीं है। ईएसआई निगम की नीति है कि किसी भी राज्य में निगम का कोई एक अस्पताल ही राज्य भर के निगम अस्पतालों के लिये स्टाफ़ की भर्ती व नियुक्तियां करेगा। हरियाणा राज्य में यह दायित्व गुड़गांव के एक अस्पताल के जिम्मे है। वहां के एम एस (मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट) ने उक्त भर्तियों का विज्ञापन केवल उन रिक्तियों के लिये दिया है जो गत 5-6 वर्षों से उक्त दोनों अस्पतालों में खाली पड़ी थीं। यानी कि इस निगम का काम मज़दूरों से हर महीने पैसा झटकने का ही रह गया था, सेवा देना उसका काम नहीं रह गया था। यदि मौजूदा डी जी दीपक कुमार की जगह अनिल कुमार या उस जैसा ही कोई नालायक व हरामखोर होता तो ये भर्तियां भी नहीं होनी थी। विदित है कि दिसम्बर 2012 में भी इसी तरह की भर्तियों के लिये आवेदन मांगे थे। करीब 17000 लोग़ों ने बैंक ड्राफ़्टों के साथ आवेदन किये थे जो डी जी अनिल कुमार ने आते ही रद्द कर दिये थे।

जानकारों के अनुसार उक्त पोस्टें विज्ञापित करने वाले गुड़गांव के एम एस को पता ही नहीं कि फ़रीदाबाद में भी कोई अस्पताल है जिसके लिये उन्हें स्टाफ़ भर्ती करना है। उनको यह जानकारी देने के लिये 8 दिसम्बर को ही निगम मुख्यालय ने एक पत्र लिख कर उन्हें चेताया भी था, परन्तु खबर छपने तक उन पर कोई असर नहीं हुआ।

बेशक उक्त विज्ञापनों में घोषित रिक्तियों को बढाने का प्रावधान है यानी कि घोषित 100 रिक्तियों के स्थान पर 200 या 300 (आवश्यकतानुसार) भर्तियां की जा सकती हैं। लेकिन यहां के अस्पताल के लिये करीब 12-13 प्रकार के ऐसे स्टाफ़ की भी आवश्यकता है जिनका उक्त विज्ञापनों में कोई ज़िक्र नहीं है। जाहिर है उन रिक्तियों के लिये अलग से विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगना आवश्यक है। लेकिन गुड़गांव के एम एस को यह बात समझने में न जाने कितना समय और लगेगा?

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि उक्त भर्तियों के लिये दिसम्बर 2012 में आवेदन मांगे गये थे, यदि नये डी जी दीपक कुमार जी, जिन्होंने जून 2015 में कार्यभार सम्भाला था, उसी वक्त रद्द किये गये निगम के पुराने विज्ञापन को बहाल करके अथवा उसी में थोड़ा-बहुत संशोधन करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करा देते तो आज न केवल गुड़गांव व मानेसर के अस्पतालों की सेवा सुचारू रूप से चल रही होती बल्कि यहां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सेवा भी सुचारू हो जाती। परन्तु सरकारी बाबूडम के चलते कदम-कदम पर बैठे बाबू रोड़े अटकाना अपना परम कर्त्तव्य एवं जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। डी जी दीपक कुमार को इन बाबुओं को समय रहते पहचान कर दुरूस्त करना चाहिये।

पीपीपी मोड का बुखार उतरना जरूरी है

इएसआईसी के इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डायलेसिस का काम पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने की सोच पूर्णतया अनुचित एवं अव्यवहारिक है। इस मोड का असल उद्देश्य होता है पबिल्क यानी सरकारी साधनों को लूट हेतु किसी प्राइवेट कम्पनी को देना। वैसे तो यह कहीं पर भी नहीं होना चाहिये, परन्तु इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो यह किसी भी हाल में कामयाब होने वाला नहीं है।

जैसा कि अस्पताल के नाम से ही जाहिर है इसमें डायलेसिस के साथ-साथ इससे सम्बन्धित पढने व पढाने का काम भी होना है। इसके लिये पूरा नेफ़रोलॉजी विभाग का बनना आवश्यक है। जब इस तरह का पूरा विभाग और पढने-पढाने वाले होंगे तो पीपीपी वाली कम्पनी अपनी लूट की दुकानदारी कैसे चला पायेगी? ऐसे में अव्वल तो कोई कम्पनी यहां आकर फ़ंसना नहीं चाहेगी; फ़िर भी यदि किसी तरह निगम के जनविरोधी कलाकार अफ़सर किसी को बहला-फुसला कर ले भी आये तो वह टिकने वाला नहीं। इसलिये बेहतर होगा कि इस वाहियात कवायद में उलझने की बज़ाय सीधे-सीधे अपना नेफ़रोलॉजी विभाग शिघ्रातिशीघ्र स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करें।

आम जनता को केवल प्राथमिक चिकित्सा

अस्पताल की नई एवं आकर्षक इमारत को देख कर कुछ इस तरह की बातें भी चलाई जा रही हैं कि ईएसआई कार्डधारकों के अलावा आमजन भी इसमें इलाज करा सकेंगे, खासकर दुर्घटना आदि के मामले में ऐसा नहीं है। यह सेवा केवल उन मज़दूरों के लिये है जिनके वेतन से हर माह साढे 6 प्रतिशत ईएसआई वसूलती है। हां मानवता के नाते, अस्पताल के आसपास हुई किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति यदि यहां आ जाये तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर अन्य अस्पतालों का रास्ता दिखाया जा सकता है।

हां, यदि अस्पताल की क्षमता से कम (कार्डहोल्डर) मरीज़ आ रहे हों तो निगम को जरूर सोचना चाहिये कि केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन्हीं दामों पर चिकित्सा देने का, जिन पर अभी तक मौजूदा प्राइवेट अस्पताल दे रहे हैं। इससे जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिल पायेगा वहीं निगम को आय होगी और प्राइवेट अस्पतालों की लूटमार घटेगी।

ऐसे बनायेंगे शहर को स्मार्ट

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम अधिकारियों व भू- माफ़ियाओं की मिलीभगत के चलते शहर में अवैध-निमाणों की बाढ आ गई है। जिसके चलते शहर का बेड़ा गर्क हो गया है। जिसका उदाहरण एन.एच.5 शिव मंदिर रोड पर स्थित एस.एस.आई प्लॉट नं. 6 में बन रहे अवैध शॉपिंग काम्पलैक्स को देखते ही बनता है। सारे नियम ताक पर रख कर अवैध निर्माण धड़ल्ले से ज़ारी है। जबकि पिछले वर्ष इसी प्लॉट में नगर निगम द्वारा तोड़-फ़ोड़ के साथ कई दुकाने भी सील की गई थी। बावजूद इसके 30 दुकाने तैयार की गई जिसमें 15 दुकाने बिक कर आबाद भी हुई। दिनांक 21.11.15 को दोबारा से प्रथम तल पर अवैध निर्माण चालू है जिसमें 30 दुकाने बनकर तैयार भी हो गई है। जबकि ड्रामेबाजी के लिये नगर निगम द्वारा कई बार इस अवैध निर्माण की फ़ोटो ग्राफ़ी भी करवाई। सूत्रों द्वारा इस शॉपिंग काम्पलैक्स को बनवाने के लिये इसके मालिक ने आधा दर्जन से अधिक पत्रकारों को भी काफ़ी रुपये बांटे इसी तरह 5 नं. के पी/16 से पी/21 तक बिल्डरों द्वारा 30 से अधिक फ़्लैट बनाकर तैयार किए गए जबकि इसी 5 नं. के जे व के ब्लॉक में पिछले 6 महीनों में 200 से ऊपर फ़्लैट व अन्य बलॉकों में 1000 से अधिक फ़्लैट बनकर तैयार हुए व कई बिक कर आबाद भी हुए जिसकी पूरी सूची मज़दूर मोर्चा के पास है। जिसमें बिल्डरों द्वारा कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं करवाई गई व सीवर पानी के कनैक्शन तक अवैध रूप से लगवा दिए गए।

बड़खल क्षेत्र से विधायक सीमा त्रिखा ने चुनावों के दौरान आश्वासन दिए थे कि उनके क्षेत्र में जुआ, सट्टा, कैसिनो, शराब तस्करी, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन धंधों को बंद करवाने के नाम पर वोट तो बटोर लिये लेकिन ये सब गोरख धंधे ज्यों के त्यों चल रहे हैं। इन धंधेबाज़ों का जमावड़ा अक्सर विधायक सीमा त्रिखा के घर पर देखा जाता है। एन.एच.5 मार्केट में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण ज़ारी है। शाम के वक्त मार्केट से निकलना तक दूभर है। शिव मंदिर रोड, 4-5 चौक, निरंकारी चौक पर दुकानदारों ने जमकर अतिक्रमण कर रखा है। पिछले दिनों थाना एनआईटी प्रभारी व एसीपी एनआईटी ने कुछ दुकानदारों व बाजारों के प्रधानों को बुलाकर अवैध कब्ज़ों व अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा भी लेकिन जिन प्रधानों को बुलाया गया उन्होंने तो खुद ही अतिक्रमण कर रखा था। वो क्यों पुलिस की हां में हां करते। थाना एनआईटी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माणों के लिए तो नहीं दुकानदारों द्वारा फुटपाथ कब्ज़े को लेकर विधायक महोदय फ़ोन कर देती है कि फुटपाथों से कब्ज़े हटवाये जाए। जबकि विधायक सीमा त्रिखा को अवैध निर्माणों को बनवाने से कई तरह के निजी फ़ायदे भी है। दुकानदारों से तो 5 साल में एक बार वोट मिलता है जो समय आने पर सीमा त्रिखा उनसे दोबारा बेटी-बहू पंजाबी होने के नाम पर बटोर ही लेगी। एक तरफ़ मुख्यमंत्री खट्टर फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का ढोल पीट रहे हैं वहीं उनकी ही पार्टी विधायक इस मुहिम में पलिता लगाने में जुटी हैं।

उजाग़र होता दलाल ट्रेड यूनियनों का चरित्र

दिल्ली (इन्कलाबी मज़दूर) आज जब चारो तरफ़ से मज़दूर वर्ग पर हमला तेज़ हुआ है तो वहीं दूसरी ओर अपने आपको मज़दूरों की हितैषी कहलाने वाली दलाल ट्रेड यूनियनें मज़दूरों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। मज़दूर वर्ग जब निर्मम शोषण-उत्पीड़न के ख़िलाफ़ खुद को अपनी चेतना के हिसाब से जिस भी रूप में संघर्ष में उतार रहा है और उसमें गुस्से को दिखा रहा है तो इस तरह की ट्रेड यूनियनें मज़दूरों की वर्गीय चेतना को कुंद करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। इस तरह की ट्रेड यूनियनों के चरित्र को दिखाते हुए एक घटना 2 सितम्बर 2015 को श्रम कानूनों के खिलाफ़ देश व्यापी हड़ताल के दौरान देखने को मिली।

बात दल्ली के औद्योगिक क्षेत्र बादली की है। यहां पर अधिकतर असंगठित क्षेत्र के मज़दूर काम करते हैं। हड़ताल में यहां के मज़दूरों ने भी भागीदारी की। मज़दूरों ने जोश-खरोश के साथ भाग लिया। इस क्षेत्र में सीटू का काम होने के चलते मुख्यत: सीटू के नेतृत्व में यह हड़ताल थी। इंकलाबी मज़दूर केन्द्र ने भी हड़ताल को समर्थन दिया तथा वहां पर अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से हड़ताल में भाग लिया तथा मज़दूरो को नेतृत्व दिया।

हड़ताल की पहले ही रूप-रेखा बना दी गयी थी कि हड़ताल पूरे दिन की होगी तथा जो फैक्टरियां खुली होंगी उनको बंद कराया जायेगा। लेकिन जो पहले से तय था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि मज़दूरों को एक बार फ़िर हताशा और निराशा हाथ लगी।

पहली बात तो यह है कि लगातार निर्मम शोषण-उत्पीड़न के चलते मज़दूरों के अंदर काफी गुस्सा था जिसके चलते वह अपनी समझ के हिसाब से लड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे लकिन सीटू जैसी ट्रेड यूनियन की बड़ी बातें यहां पर खोखली साबित हुयीं और पूरे जुलूस के दौरान अराजकता का माहौल बना रहा। मज़दूरों की शिकायत थी कि अगर हमें फैक्टरियां बन्द ही नहीं करवानी हैं तो इस हड़ताल का क्या मतलब है। सारे मज़दूर चाहते थे कि सारी फैक्टरियों को भी बन्द करवाया जाये। इक्का-दुक्का फैक्टरी को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते मज़दूरों में सीटू नेताओं के खिलाफ़ काफ़ी गुस्सा दिख रहा था।

हड़ताल की पहले ही रूप-रेखा बना दी गयी थी कि हड़ताल पूरे दिन की होगी तथा जो फैक्टरियां खुली होंगी उनको बंद कराया जायेगा। लेकिन जो पहले से तय था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि मज़दूरों को एक बार फ़िर हताशा और निराशा हाथ लगी।

दूसरी बात जो देखने में आयी वह मज़दूरों को आश्चर्यचकित करने वाली थी। सीटू के 3-4 बड़े नेता जो कि डील-डौल, रहन-सहन, पहनावे आदि में किसी फैक्टरी मालिक से कम नहीं लग रहे थे बल्कि कुछ मज़दूरों ने तो उनको फैक्टरी मालिक ही समझा तो उनको बताना पड़ा कि हम आपके साथ ही हैं, सीटू से हैं। हो यह रहा था कि सारे मज़दूर कड़ी धूप,धूल-धक्कड़ में जुलूस की शक्ल में फैक्टरी-फैक्टरी जा रहे थे लेकिन सीटू के ये 3-4 नेता अचानक से तभी प्रकट हो रहे थे। जब किसी चौराहे पर सभा हो रही थी। उनको सीटू का स्थानीय नेता फ़ोन कर रहा था कि अब आ जाओ। वे भी तभी 10-15 मिनट के लिये दिख रहे थे। भाषण देकर फ़िर गायब हो जा रहे थे शायद अपनी वातानुकूलित गाड़ियों में। काफ़ी दिलचस्प था यह सब कुछ। कुछ मज़दूर तो आपस में मज़ाक भी कर रहे थे कि कितने महान हैं ये मज़दूरों के हितैषी ट्रेड यूनियन नेता।

तीसरा, जो मज़दूरों को सबसे निराश करने वाली बात थी। वह यह कि आधा दिन के बाद सीटू नेताओं ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। जिसको लेकर मज़दूरों में काफ़ी गुस्सा दिखा। वह हड़ताल को पूरा दिन चलाना चाहते थे। लेकिन नेतृत्वकारी नेतागण वहां से हड़ताल खत्म करने की घोषणा करके पहले ही चल दिये थे। कुछ मज़दूर इधर-उधर हो गये लेकिन भारी संख्या में मज़दूर वहीं पर डटे रहे। और गुस्से में सीटू के नेताओं को गाली देने लगे कि अब मालिक आधा दिन बाद फैक्टरी शुरू कर देगा बल्कि कुछ मज़दूरों के पास फैक्टरी से फ़ोन भी आने लगे कि काम पर आ जाओ।

इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के कार्यकर्ता लगातार मज़दूरों से बात कर रहे थे और उनको नेतृत्व दे रहे थे। उसके बाद मज़दूरों के कहने पर सारे लोग सीटू के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गये। लेकिन वहां भी मज़दूरों को निराशा ही हाथ लगी। ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ काफ़ी तीखी नोंक-झोंक हाने के बाद भी वहां से मज़दूरों को खाली वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार मज़दूरों ने अपने आपको एक बार फ़िर छला हुआ महसूस किया तथा आपस में बात करने लगे कि अगली बार से इस तरह की ट्रेड यूनियन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। काफ़ी मज़दूरों ने इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के कार्यकर्ताओं से बातचीत की तथा आगे भी मिलने की इच्छा जाहिर की।

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से ये दलाल ट्रेड यूनियनें लगातार मज़दूरों के साथ विश्वासघात कर रही हैं जिसके चलते मज़दूरों के अंदर संगठन बनाने/यूनियन में शामिल होने को लेकर एक अविश्वास बनता चला जा रहा है जोकि पूंजीपति वर्ग चाहता है।

इसलिये आज जरूरत है इस तरह की दलाल ट्रेड यूनियनों का मज़दूरों के बीच भण्डाफ़ोड किया जाये तो मज़दूरों की असली लड़ाई लड़ने वाले संगठनों को स्थापित किया जाये।

-विजय